

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खनन अधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खनन अधिकारी रुद्रप्रयाग के माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार मौर्य ले0प0 व श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.05.17 से 31.05.17 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मक:** डी0डी0ओ0 का कार्य नहीं किया जा रहा है।

वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** - सम्पूर्ण रुद्रप्रयाग

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षों मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	लक्ष्य	अर्जित राजस्व (रु लाख में)
2012-13		207.62
2013-14		324.07
2014-15		628.86
2015-16		989.21
2016-17		971.05

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ---A---श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव (खनन) – अपर सचिव/निदेशक – जिला खनन अधिकारी

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में सम्पूर्ण रुद्रप्रयाग जनपद को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खनन अधिकारी रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: माह 03/14, 10/15 और 3/17 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षाभाग-II 'ब'

प्रस्तर 01:- वभागीय उदासीनता के फलस्वरूप राजस्व क्षति 13.33 लाख एवं ब्याज की हानि

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं० 197/VII-1/130-ख/2013 देहरादून दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के दिशा-निदेशों के अनुपालन में राजस्व भूमि पर राजस्व हित एवं राज्य विकास के लिये खनन/चुगान के लिये पट्टा देने के लिये स्थल का सयुक्त निरीक्षण कर एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के आदेश सं 1573/तीस-03/2013-14 दिनांक 18.01.2014 को (i) श्री धीर सिंह पुत्र श्री रतन सिंह उखीमढ रुद्रप्रयाग को खसरा सं० 1370 के रकवा 0.080 हे० के राजस्व नाप भूमि में 2280 टन अधिकतम मात्रा प्रतिर्ष उपखनिजों के चुगान की स्वीकृत पट्टा रजिस्टर्ड कराने के उपरान्त प्रथम मासिक किश्त ` 76125 जमा करने के उपरान्त तथा दो मासिक किश्त 152250 प्रतिभूति की धनराश जमा करने के उपरान्त तीन वर्षों या 30 सितम्बर 2016 तक, जो भी पहले हो, के लिये निम्न शर्तों के साथ खनन/चुगान का आदेश दिया गया था।

- (क) पट्टाधारक द्वारा उपरोक्त स्वीकृत शर्त में उत्तराखण्ड परिहार्य नियमावली 2001 तथा खनिज नीति-II के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन खनन/चुगान का कार्य करेगा तथा वार्षिक अपरिहार्य भाटक का धनराश भुगतान व मासिक समान किश्तों के रूप में अग्रिम प्रत्येक माह की 20 तारीख तक राजकीय कोषागार में जमा करेगा।
- (ख) खनन पट्टा धारक द्वारा निर्धारित तिथि तक अग्रिम में मासिक किश्त न जमा किये जाने की स्थिति में खान अधिकारी/अध्यक्ष खान अधिकारी 10 दिन के भीतर वलम्ब शुल्क 15% वार्षिक ब्याज सहित जमा किये जाने का नोटिस जारी करेगा। यदि नोटिस के उपरान्त भी अग्रिम जमा नहीं किया जाता तो पुन खान अधिकारी 7 दिन के भीतर वलम्ब शुल्क 18% वार्षिक ब्याज की दर से नोटिस जारी करेगा उक्त के उपरान्त भी यदि अग्रिम मासिक किश्त जमा नहीं किया जाता तो जिला अधिकारी द्वारा प्रतिभूति व अग्रिम धनराश का समायोजन करते हुये निरस्त कर दिया जायेगा।
- (ग) खनन पट्टा निरस्त होने तथा अग्रिम जमा जब्त होने के उपरान्त भी कोई देयता बनती है तो खनन पट्टा धारक से पृथक से भू- राजस्व की क्षति खनन राजस्व की वसूली की कार्यवाही की जायेगी तथा पट्टाधारक को 05 वर्ष हेतु काली सूची में डाल दिया जायेगा।

- (घ) मा सक अ ग्रम धनरा श को जमा करने के उपरान्त ही खनन/चुगान की मात्रा के परिवहन हेतु फार्म एम0एम0 11 निर्धारित मूल्य जमा कर कार्यालय से प्राप्त करेगा।
- (ङ) उप खनिजों का चुगान/खनन पट्टा अव ध के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 01 अक्टूबर से 30 जून (09माह) तक रहेगा।

जिला खनन अधिकारी, रुद्रप्रयाग की नमूना जांच में पाया गया कि निवदा की शर्तों के अनुसार पट्टा तीन वर्ष या 30 सितम्बर 2016 तक की अव ध हेतु था, इस लये माह 01/2014 (पट्टा आदेश माह) से 30 सितम्बर 2016 तक के मध्य वर्षा ऋतु (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) को छोड़ कर कुल 24 माह में चुगान/खनन किया गया था परन्तु 24 माह का कस्त न जमा करके मात्र 11 माह की कस्त 837375/- जमा किया गया था। इस प्रकार 13 माह का (10/14 का तथा 04/15 से 06/16 तक) कुल धनरा श 989625/- को राजस्व के रूप में कोषागार में जमा नहीं किया गया तथा उक्त पर जमा कये जाने की ति थ तक ब्याज भी देय है।

(ii) श्री अनुसूया प्रसाद मालसी पुत्र श्री गुणानन्द मालसी की पत्रावली की जांच में पाया गया कि पट्टा धारक द्वारा 04/17 तक में चार माह का मा सक कस्त जमा नहीं किया गया था जिस कारण ₹342504/- की राजस्व क्षति हुआ था तथा उक्त पर जमा करने की ति थ तक ब्याज भी देय होगा।

उक्त अनियमिता के संबंध में इंगत कये जाने पर इकाई आकड़ों तथ्यों की पुष्टि करते हुये उत्तर दिया गया कि एम0एम0-11 निर्गत करने की ति थ बता पाना संभव नहीं है। प्रतिभूति एवं अग्रम का समायोजन नहीं किया गया है और न ही भू-राजस्व की क्षति वसूली की कार्यवाही की गयी है तथा पट्टा धारक को काली सूची में भी नहीं डाला गया है तथा सम्प्रेक्षा ति थ तक खनन पट्टा भी निरस्त नहीं किया गया है।

उत्तर स्वतः ही प्रकरण स्वीकार्य करता है। अतः उक्त दोनों प्रकरणों में वभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹13.33 लाख एवं जमा कये जाने की ति थ तक ब्याज का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 02-स्टोन क्रेशर के आवेदन शुल्क के रूप में कम जमा से राजस्व क्षति 2.00 लाख

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या 1026/VII-1/2015/68-रिट /2008 देहरादून, दिनांक 31.07.15 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र-क) के लिये स्टोन क्रेशर के आवेदन मवीनीकरण हेतु 200 टन प्रतिदिन तक क्षमता के लिये शुल्क 2.50 लाख निर्धारित था।

कार्यालय जिला खनन अधिकारी, रुद्रप्रयाग की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया गया क उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1352/VII-1/40-स्टोन क्रेशर/2015 देहरादून, दिनांक 16 सितम्बर 2015 के द्वारा आवेदक नीलकण्ठ स्टोन क्रेशर द्वारा श्रीमती आरती उनियाल को ग्राम चम सल (सारी) में 200 टन प्रति दिन क्षमता का स्टोन क्रेशर स्थापना संचालन हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिये अनुज्ञा स्वीकृत किया गया था। आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में मात्र 0.50 लाख चालान द्वारा जमा किया गया था, जबकि कार्यालय ज्ञाप के अनुसार स्टोन क्रेशर के आवेदन मवीनीकरण पर शुल्क 2.50 लाख जमा किया जाना अपेक्षित था।

उपरोक्त प्रकार से 2.00 लाख आवेदन शुल्क के रूप में कम जमा किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगत किये जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि "परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी एवं आवेदक द्वारा अवशेष 2.00 लाख जमा नहीं किया गया है।"

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 03-स्टाम्प शुल्क का अनारोपण ₹1.33लाख

इण्डियन स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 के अनुसार वध या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत पुलिस अधिकारी के सवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष उसके कर्तव्य के सम्पादन में कोई ऐसा वलेख प्रस्तुत किया जाये या आ जाये, जो उसकी राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह वलेख यथा वध स्टाम्पित नहीं है, से जव्त करेगा।

पुन धारा 35 के अनुसार वध या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे वलेख को जो शुल्क से प्रभार्य है, साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जायेगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा या किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा उसको कार्यन्वित रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणित नहीं किया जायेगा, जब तक वह वलेख यथा वध स्टाम्पित न हो। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17(1)(घ) में यह प्रावधान किया गया है कि वर्षा नु0वर्ष या एक वर्ष से अधिक से अधिक किसी अवध के लिये या वार्षिक कराया सुरक्षित करने वाली अचल सम्पत्त की लीज के लेखपाल का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। लीज के जो वलेख एक वर्ष से कम अवध के लिये हैं उनका रजिस्ट्रीकरण ऐच्छिक है किन्तु उसके प्रतिफल की धनराश पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जाना अपेक्षित है।

पुन महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड के पत्रांक 82/म0नि0नि0/2013-14 दिनांक 23.12.13 जो समस्त जिला अधिकारी को संबन्धित है के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि समस्त कार्यालयध्यक्ष भारतीय स्टाम्प अधिनियम का धारा 33 के आलोक में उनके कार्यालय में वगत 8 वर्षों में निष्पादित किये गये व भन्न प्रकार के वलेखों का परीक्षण कर ले एवं यदि किसी प्रकरण में स्टाम्प कमी का मामला दृष्टिगोचर हो तो संबन्धित वलेख की प्रति अपनी आख्या सहित यथाशीघ्र अपने जनपद के कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

कार्यालय जिला खनन अधिकारी, रुद्रप्रयाग की नमूना लेखापरीक्षा में कार्यालय के स्टे केशर स्थापना भण्डारण की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि सात स्टोन केशर भण्डारण के स्वामियों को स्टोन केशर भण्डारण हेतु कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी भूम

कराये पर दी गयी तथा अनुबन्ध/करायेनामे पर मात्र 10/- से लेकर 150/- तक का स्टाम्प स्टाम्पित किया गया था जब क नियमानुसार अनुलग्नक-1 के कालम -9 के अनुसार स्टाम्प देय था एवं कालम-10 के अनुसार स्टाम्प शुल्क का कम था। उक्त प्रकार से वर्णित मामले कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित नहीं कये जाने से 1.33 लाख के स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई तथा इन वलेख पत्रों को उप निबंधक कार्यालय में पंजीकृत न कराये जाने के कारण निबंधन फीस के रूप में भी राजस्व क्षति हुई।

इसे इंगत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क "उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-2 की अधिसूचना सं 3252X/II-II/22-ख/01/2011, दिनांक 23 दिसम्बर. 2011 अतिरिक्त प्रावधान बिन्दु (4) के अनुसार निजी नाप भूम में वज्रपतिकरण की कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा भूस्वामी अथवा भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदन करने पर जिला अधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर खनन निदेशक की संस्तुति के उपरान्त खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कये जायेगे।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि उनके उत्तर में निजी नाप भूम में वज्रपतिकरण हो या नहीं के बारे में बतलाया गया है न क कम स्टाम्प के बारे में।

प्रकरण उच्चाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 04- खनिज का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों से कम शमन शुल्क की वसूली 40000/-

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, अधिसूचना संख्या 1725/VII-1/16/158-ख /2004 देहरादून दिनांक 13 नवम्बर 2016 के नियम 13-ज (1) के अनुसार 06 पहिया ट्रक पर अधरोपत कये जाने वाला अर्थदण्ड 30000 तथा वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य, 06 पहिया से अधिक ट्रक, डम्पर, हाइवा आदि हेतु अर्थदण्ड 50000 तथा वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य निर्धारित किया गया था।

उक्त के अनुसार डम्पर एवं हाईवा पर अर्थदण्ड 50000 निर्धारित था।

कार्यालय जिला खनन अधिकारी, रुद्रप्रयाग की नमूना लेखापरीक्षा में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पत्रावलयों की जांच में पाया गया कि तीन डम्पर जो सभी 06 पहिया थे बिना वैध कागजात के परिवहन करते हुए पकड़े गये जिनमें डम्पर सं UA13-0407 जो दिनांक 26.03.17 को पकड़ा गया, से परिवहन का अर्थदण्ड 50000 निर्धारित कर वसूला गया, किन्तु डम्पर संख्या UK13CA-0572 जो दिनांक 20.11.16 एवं डम्पर सं UK13CA023 पकड़ा गया से परिवहन का अर्थदण्ड ₹30000 प्रत्येक का निर्धारित कर वसूल किया गया था।

उपरोक्त प्रकार से अधिसूचना के अनुसार अर्थदण्ड न लगाने से जो दिनांक 20.12.16 को 40000 की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगत कये जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बतलया कि शासनादेश में दिये प्रावधानों के अनुसार वाहन के प्रकार व पहियों के अनुसार संबंधित वाहनों से अर्थदण्ड वसूला गया है, उक्त सभी वाहनों से नियमानुसार वसूली की गयी है, जिसका अर्थदण्ड वसूली उपरान्त जमा खजाना किया गया है।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि सभी तीन वाहन 06 पहिया डम्पर थे तब एक डम्पर से अर्थदण्ड 50000 तथा दो डम्परों से अर्थदण्ड 30000 (प्रत्येक

से) निर्धारित कर वसूल करने में भ्रष्टता का कारण थी, इकाई द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : प्रथम लेखापरीक्षा

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
लागू नहीं		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

व्यय से संबंधित: - शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला खनन अधिकारी रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएं:
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री वरेन्द्र कुमार सिंह	खान अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला खनन अधिकारी रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र